अपराह्न 12.02 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

दसवां से तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू और कश्मीर में एक तरफा संघर्ष विराम

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अपने अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर के पूरे मामले पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। 58 हजार सिख परिवार वहां से हिजरत करके आ रहे हैं, यह बहुत ही सीरियस मामला है। वहां उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनके बच्चों की जान सुरक्षित नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह बहुत गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने उस समय अन्य बातों के साथ साथ, माननीय संसद सदस्यों के समक्ष यह बात भी रखी थी कि :-

"सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक बहुकोणीय नीति अपना रही है। इसके एक भाग के रूप में इसने 19 नवम्बर, 2000 को रमजान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में संघर्ष की पहल न करने की एकतरफा घोषणा करके एक प्रमुख शांति मिशन आरंभ किया है। इस सार्हामक पहल की अवधि दो बार बढ़ाकर 26 फरवरी, 2001 तक रखी गई है। जैसी कि प्रत्याशा थी, इसका जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भरपूर स्वागत किया जो अपने इस सुंदर राज्य में उग्रवाद और हिंसा की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पूरा समर्थन दिया है क्योंकि वह इसे कश्मीर मामले के शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान के लिए भारत की सच्ची वचनबद्धता के एक और प्रमाण के रूप में देखता है।"

राष्ट्रपति जी ने तब माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराया था कि :-

"जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अधिकाधिक भाड़े के विदेशी गुटों तक सीमित होकर रह गया है। इससे राज्य में लोकतांत्रिक कार्यकलाप की गुंजाइश बढ़ गई है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में राज्य के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं फिर से यह दोहराता हूं कि सरकार राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से वार्ता के लिए तैयार है।"

सरकार ने जम्मू व कश्मीर में विभिन्न गुटों से बातचीत शुरू करके इस मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

सरकार ने शांति प्रक्रिया को जारी रखने तथा हमारे सुरक्षा बलों द्वारा सैनिक कार्रवाई को स्थगित रखने की अवधि को और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है। इस संबंध में सरकार ने 21 फरवरी, 2001 को सभी राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक में स्थिति की विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उनसे सलाह-मशविरा किया।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूरे मामले के सभी पहलुओं पर गहराई से सोच-विचार करने के बाद सरकार ने इस अवधि को मई के अंत तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी लोगों जो शांति चाहते हैं, को यह मौका नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि हमारे धैर्य की भी कोई सीमा है।

मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शांति प्रक्रिया केवल उन लोगों के लिए है जो इससे लाभ उठाना चाहते हैं। हम इस प्रक्रिया में न तो बाधा आने देंगे, न ही इसमें कोई कमी आने देंगे या इसका दुरुपयोग होने देंगे। ऐसे संगठनों या तत्वों, जो शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं या जम्मू व कश्मीर में हिंसा को जारी रखने और निर्दोष लोगों की हत्या करने का इरादा रखते हैं, के लिए मेरा संदेश साफ और स्पष्ट है। अगर आप जम्मू व कश्मीर राज्य में या कहीं भी किसी भारतीय नागरिक को चोट पहुंचाएंगे अथवा हिंसा या आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई करेंगे तो सुरक्षा बलों को स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि वे निर्णायक कार्रवाई करें और ऐसे दुष्कृत्यों को विफल कर दें। कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। जो लोग यह सोचते हैं कि आज हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद का खात्मा करने के लिए कम दृढ़-संकल्प हैं, तो वे केवल अपने-आप को धोखे में रखे हुए हैं।

मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अभी भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा और हिंसा का रास्ता छोड़ देगा, भारत के खिलाफ अपने निरंतर शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकेगा, सीमा-पार से आतंकवाद को शह और मदद देना बंद करेगा तथा शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के तहत द्विपक्षीय बातचीत का रास्ता अपनाएगा। इस तरह से एक अनुकूल माहौल बनेगा ताकि एक व्यापक बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके जिससे समस्याओं का स्थायी हल निकल सकेगा।

शांति प्रक्रिया से जम्मू व कश्मीर में हमारे नागरिक चैन से रह सकेंगे। वे यही चाहते हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए न कि आतंकवादियों या भाड़े के विदेशी सैनिकों की।

शांति बहाल करना ही हमारा उद्देश्य है, शांति और बातचीत के लिए हम हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं क्योंकि जम्मू व कश्मीर के लोग वास्तव में यही चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद सं 7-श्री नारायण दत्त तिवारी।

अपराह्न 12.08 बजे

लोक लेखा समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं "सीमा-शुल्क प्राप्तियां-गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क लगाना-ऊनी अपशेष अथवा ऊन" संबंधी लोक लेखा समिति (आठवीं लोक सभा) के 111वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : सिख परिवार अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। *(व्यवधान)* वहां सिख मारे जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। सभा में विवरण के पश्चात प्रश्न उठाने की कोई परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : देश के किसान मर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। हमने टी वी में भी देखा, आप सुबह से हाउस को डिसटर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं किसी उचित समय पर जम्मू-कश्मीर मामले पर चर्चा की मांग करता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जे०एस० बराड़, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार ने उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री जे०एस० बराड़ : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर, सिक्योरिटी फोर्सेस में जो टरबन पहने हुए हैं, उन सबको खतरा पैदा हो गया है। उनकी सिक्योरिटी का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। इस प्रकार का खतरा 140 गांवों में है। उनकी सिक्योरिटी के बारे में आज तक क्या किया गया है? *(व्यवधान)*